उत्तर प्रदेश में मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई परियोजनाएं

1720. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मध्यम और बड़े आकार की अनेक सिंचाई परियोजनाएं अत्यधिक खर्चीली और विलंबकारी सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बृहद सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की सामान्यतया अवधि 10—15 वर्ष होती है और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 5 वर्ष होती है । इस आधार पर राज्य सरकार ने 1978-79 से पूर्व 14 अनुमोदित बृहद सिंचाई परियोजनाएं शुरू की थी और सातवीं योजना से पूर्व एक अनुमोदित मध्यम सिंचाई तथा 3 अनुमोदित विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी समय सीमा से पीछे चल रही माना गया है । संशोधित लागत के अनुसार उनकी अनुमानित लागत प्रारम्भिक अनुमानित लागत 1055.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 4617.40 करोड़ रुपये हो गयी है । निर्माण के दौरान मूल्य बढ़ जाना तथा संसाधनों की कमी के कारण विभिन्न परियोजनाओं के लिये पूर्वनिर्धारित निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप अपर्याप्त वार्षिक नकदी प्रवाह लागत वृद्धि के मुख्य कारण हैं ।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्रों को 2599.34 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं । राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं को विशेष सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है । आठवीं योजना नीति में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है । राज्य को योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए परियोजनावार परिव्यय का कड़ाई से पालन करना है ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके ।

Recommendation of Vaidyanathan Committee

1721. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what are the recommendations of Vaidyanathan Committee with regard to nationalisation of the rate structure for irrigation water; and

(b) what recommendations have been accepted by Government

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Some salient features of the report of Vaidyanathan Committee include : treating water rates as users charge; the objective of water charge is ultimately to recover cost; linking revision of water rates to the improvement of the quality of service; revision and implementation of water rates in phases; consolidation of the system of farmer group management; upgrading the system to higher level efficiency in water use and productivity; setting up of experts group at the State level for working out norms and procedure for periodic monitoring; setting up of autonomous boards at the State level to review policy regarding cost of water, revising water rates and introducing a minimum financial return criteria.

(b) 'Irrigation' being a state subject, decision on water rates can be taken only in consultation with the State Governments and the Administration of Union Territories. With a view to go into the report of the Committee and to have a broad spectrum of the views on various recommendations made by the Committee, the Planning Commission has constituted a group of officials under the Chairmanship of the Secretary, Planning Commission.

विश्व बैंक की सहायता से कार्य करने वाली चालू सिंचाई परियोजनाएं

1722. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उसकी सहायता से चल रही चालू सिंचाई परियोजनाओं पर कोई आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन पर ये आपत्तियां की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां । विश्व बैंक ने

निर्माणाधीन दूसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई संयुक्त परियोजना के संबंध में तकनीकी व्यवहार्यता पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी गयी है कि वह विश्व बैंक द्वारा सुझाये गए विभिन्न तकनीकी अध्ययनों की रिपोर्टों की प्रतियां केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध करायें । इनके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए कुछ और अध्ययन किए हैं ।

Human Rights Violation in Narmada Valley

1723. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Times of India dated the 19th May, 1993, captioned 'India blind to plight of tribals hit by dam project';

(b) whether it is a fact that Narmada International Human Rights Panel, Washington has decided to begin monitoring human rights violations regarding the resettlement of the displaced persons in Narmada Valley; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes Sir.

(b) No such proposal has been received.

(c) The Sardar Sarovar Project is being constructed under the Narmada Water Dispute Tribunal Award which laid down guidelines, for resettlement and rehabilitation of project affected people of Sardar Sarovar Project taking into account the traditional rights of the tribals. The State Governments of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra which are parties to the Narmada Water Dispute Tribunal Award have offered much more liberalised resettlement and rehabilitation packages to the project affected people with a view to improve their standard of living and quality of life. Relocation of tribals is, therefore, fully justified in their own interest and national development and there is no violation of human rights.

Yamuna River Board

1724. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Yamuna River Board has been constituted for the integrated development and management of river Yamuna;

(b) if so, what are the names of the members of the Board;

(c) what are the terms of reference; and

(d) by when the report of this board is likely to be presented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No Sir. The Yamuna River Board has not been constituted so far.

(b) to (d) Does not arise.

Setting up of National Ground Water Training Institute in A. P.

1725. DR. NARREDDY THULASI REDDY :
SHRI N. GIRI PRASAD :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government has decided to set up a National Ground Water Training Institute to provide a specialised training course to ground water engineers, to conduct research and development of technologies and to provide consultancy services to State Governments;

(b) whether the Government of Andhra Pradesh offered to provide necessary land near Shameerpet (Ranga Reddy District) for setting up such institute; and

(c) what steps have been taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes Sir. The Government has sanctioned a scheme for the setting up of a National Training Institute for Ground Water for organising activities for upgrading the knowledge and skill of ground water professionals in planning, investigation, develop-